(गोरख पांडेय की कविता)

तुम जहां कहीं भी हो

तुम जहां कहीं भी हो
मैं तुम्हें चाहता हूं
तुम सबको चाहता हूं मैं
एक अंधेरे कमरे में
साल–दर–साल गुज़री
पीली बीमार रोशनी और घुटी हुई आवाज
जनमे अजनमे बच्चे के
लिए ख़ून बहाती
तुम जहां भी हो
मैं तुम्हें चाहता हूं

लहर–दर–लहर आदमी के हाथों के
श्रम और दिमाग़ से फूटते
कमल के फूल पर बैठी
तुम सुंदर और मोहने वाली
रोटी और नमक से मेहनत
को करने लायक और
दुनिया को जीने लायक बनाती
तुम जहां भी हो मैं तुम्हें चाहता हूं

मैं तुम सबको चाहता हूं
सदियों से चुप
होठों और आंखों और हाथों में
बोलती
चुप मगर हमारे सबसे पहले
आंख खोलने वाले शब्दों की मां
धीरज को धीरे–धीरे
इस्पात बनाती
इस्पात और आंसू
और कोड़ों की ज़िदा याद्दाश्त
तुम जैसे–जैसे आंगन बुहारती हो
रोशनी के लिये घरों को
खोलती हो
प्यार के लिये दिलों को
तुम जहां भी हो
मैं तुम्हें चाहता हूं
मैं तुम सबको चाहता हूं
अंधेरे कमरों और
बंद दरवाज़ों से
बाहर सड़क पर
जुलूस में और
युद्ध में तुम्हारे होने का
दिन आ गए हैं
तुम आओ
इस्पाती मोहक सौंदर्य
आओ, घुटन और
चुप्पी के सिलसिलों
आओ, मेरे दिल के
हज़ार टुकड़ों
बंद रोशनियों दुनिया भर की
सबके लिए आज़ादी का
अंतरिक्ष खोलो
तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें, तुम सबको चाहता हूं

संभावित रचनाकाल :1973

पेज 1 का शेष

कार्पोरेट स्कैम पर कैग चुप रहा और मोदी भी

राजनीतिकों, सत्तावान भी और विपक्ष के भी, की चुप्पी भी कोई रहस्य नहीं। न मीडिया और न सिविल सोसायटी का मामले को न उछालना कोई आश्चर्य की बात है। इन सभी पर प्राइवेट मोबाइल कम्पनियों का व्यवसायिक शिकंजा काम करता है। और भला अदालतें क्या कर रही हैं? दिल्ली उच्च न्यायालय में कितने ही मामले मिल जायेंगे जिनमें एम टी एन एल / बी एस एन एल की टेंडर-प्रक्रिया को पटरी से उतारने वाले आदेश दिये गये हैं। यानी वे प्राइवेट मोबाइल कम्पनियों के अन्तिम संकटमोचक का काम बखूबी करते आ रहे हैं। अब क्या यह भी बताना पड़ेगा कि ऐसे काम करने की एक वाजिब कीमत अदा की जाती है।

घोटाला नं. 2. कोयले और लोहे की खानों की लूट का घोटाला सिर्फ़ इतना नहीं है कि मनमाने तरिके से इनका आवंटन किया गया। हालांकि राजनीतिकों के आरोपों-प्रत्यारोपों, मीडिया की सुर्खियों और अदालतों की निगरानियों में दर्ज सी बी आई मुकदमों से यही परिलक्षित होता है। दरअसल असली घोटाला कुछ और है।

क्योंकि खानों का आवंटन मनमाने ढंग से करने के लिये जनहित का तर्क जरूरी है, लिहाज़ा सम्बन्धित महाकार्पोरेट स्टील प्लांट या ताप बिजलीघर को बनाने की परियोजना का सहारा लेता है। सम्बन्धित सरकारें इन परियोजनाओं को विकास एवं रोज़गार के नाम पर आनन-फ़ानन में स्वीकृति दे देती हैं। अब शुरू होता है असली खेल। परियोजनाओं की आड़ में खनिज की लूट।

स्टील प्लांट के लिये लौह-अयस्क से भरपूर दसियों हज़ार एकड़ का क्षेत्र सम्बन्धित महाकार्पोरेट को दे दिया जाता है। इसी प्रकार ताप बिजलीघर के लिये दसियों हज़ार एकड़ का कोयला क्षेत्र भी सम्बन्धित महाकार्पोरेट को देने में सरकारों को कोई दुविधा नहीं होती। न स्टील प्लांट कभी लगता है और न ताप बिजलीघर कभी बनता है। पर खदानों से माल धड़ाधड़ निकाला जाना शुरू हो जाता है। किसी भी ऐसी खान में प्रतिदिन हज़ारों डम्परों को लगा देखा जा सकता है। आगे होते हैं ट्रकों के विशाल काफ़िले और भारतीय रेल की मलगाड़ियां इन्हें निर्यात के लिये बन्दरगाहों व घरेलू बाजारों तक पहुंचाने में सेवारत।

सारा खेल सरेआम। सारा माल कबाड़े के नाम पर। सारा मुनाफ़ा महाकार्पोरेट की जेब में। सारी सरकारें चुप क्योंकि कहीं भाजपाई सत्ता में तो कहीं कांग्रेसी। मीडिया में एकदम उदासीनता क्योंकि मीडिया के मालिक यही टाटा, बिड़ला, जिंदल, अडानी, अम्बानी, जिनके पास मीडिया का स्वामित्व। यहां तक कि अदालतें भी इस सवाल को अंजाम तक नहीं पहुंचाती कि सारा खनिज किस खाते में निकाला और बेचा जा रहा है। विडम्बना यह कि अधिकांश माल चीन जा रहा है, जिसके सीमा पर 'नापाक' इरादों को लेकर नरेन्द्र मोदी ललकार और हुंकार रैलियां करते घूम रहे हैं।

घोटाला नं. 3. अम्बानी परिवार भारत के व्यवसायिक परिदृष्य पर घोटालों का पर्यायवाची माना जाता है। एक लेखाकार के रूप में जीवन शुरू करने वाले धीरूभाई अम्बानी ने छोटे-मोटे अफ़सरों व नेताओं को घूस देने का सिलसिला उन मंजिलों तक पहुंचाया कि भारत का बजट बनाने वाला वित्त मंत्रालय का हर बाबू उसकी जेब में होता था। धीरू भाई की मौत के बाद उसके दोनों बेटों मुकेश व अनिल ने बाप की कार्यशैली में चार चांद लगाना जारी रखा है।

अम्बानी भाइयों का आज भारतीय तंत्र पर शिकंजा इस कदर कस गया है कि गत वर्ष जब केन्द्रीय तेलमंत्री जयपाल रेड्डी ने उनकी गुलामी में कोताही दिखाई तो मंत्रिपरिषद के पुनर्गठन के नाम पर उनका तबादला अन्यत्र कर दिया गया। अब उनके घर पानी भरनेवाला वीरप्पा मोइली तेलमंत्री है। देश के हर प्रमुख टी वी चैनल व समाचार पत्र पर इन भाइयों का स्वामित्व है। यानी उन्हें आईना दिखाने वाला कोई नहीं।

उसकी दादागिरी की इन्तहा देखिये कि इस दौरान उसने गैस का उत्पादन पूरी तरह बंद किया हुआ है।

यथा नाम तथा काम। घोटालों के पर्यावाची के घोटाले भी लाखों करोड़ से कम नहीं हो सकते। और होंगे भी डंके की चोट पर। मुकेश अम्बानी ने देश के पूरे गैस बेसिन के दोहन का लाइसेंस हथिया रखा है सरकार से करार के तहत उसे 4.6 डालर प्रति यूनिट के हिसाब से एक निश्चित उत्पादन करना है; हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 2.6 डालर प्रति यूनिट का भाव है। पर हद तो तब हुई जब पहले मुकेश ने करार से दुगना भाव मांगना शुरू किया और अब इसे बढ़ा कर चौगुना कर दिया है। उसकी दादागिरी की इन्तहा देखिये कि इस दौरान उसने गैस का उत्पादन पूरी तरह बन्द किया हुआ है।

अब घोटाले की इम्तहा देखिये केन्द्र सरकार, बजाय मुकेश से हर्जाना वसूलने के, उसकी पसंद का एक अन्तर्राष्ट्रीय पंचाट बैठाने जा रही है जो करार की दरों को बढाने की सिफ़ारिश करेगा। जाहिर है मुकेश अम्बानी को चौगुणी न सही तिगुणी दर तो मिलेगी ही। तभी वह कृपापूर्वक गैस का उत्पादन शुरू करेगा। इस तरह उसे पूरे देश को ब्लैकमेल करने का लाइसेंस दिया जा चुका है। कहां एक मुश्त सैंकड़ों-हज़ारों करोड़ का घोटाला और कहां रोज़ाना सैंकड़ों करोड़ का घोटाला जो दशकों तक चलता रहेगा। कहां है नरेन्द्र मोदी? कहां है केजरीबाल? कहां है 'राष्ट्रीय' मीडिया! कहां है न्याय की अदालतें!

ब्रैडमैन से ब्रांडमैन तक सचिन... सचिन...

लिहाज़ा क्रिकेट के मलाईदार प्रशासकीय पदों को लेकर खूब रस्साकशी देखी जा सकती है। इसी तरह कप्तानों और कोचों के विवादों ने भी समय-समय पर तूल पकड़ा। हरेक को क्रिकेट के पैसे से अपना हिस्सा लेने की जल्दी रही। पर इस सब के बीच सचिन को किसी विवाद में घसीटा नहीं जा सका। उनकी छवि एक विनम्र पेशेवर की रही। सचिन केवल ब्रैडमैन बन कर नहीं रुके। वे एक बहुत बड़े ब्रांड बन कर उभरे। ब्रांडमैन के रूप में उनकी दौलत 160 मिलियन डॉलर (करीब 1000 करोड़ रुपये) आंकी जा रही है। 2011 में उन्हें और मौजूदा कप्तान धोनी को विश्व के 100 सबसे अमीर खिलाड़ियों की सूची में रखा गया था। ब्रांड व्यवसाय से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि खेल से सन्यास लेने के बाद भी सचिन ब्रांड की लोकप्रियता और उसी अनुपात में कमाई में बढोत्तरी ही होगी। विवादों से दूर और स्वच्छ छवि को भला कौन नहीं अपनाना चाहेगा।

ब्रांड के रूप में बदलने में अनुकूल परिस्थितियां सचिन के काम आईं। एक तो 1983 में भारत विश्वकप चैम्पियन बना था और इसने क्रिकेट की लोकप्रियता को शिखर पर पहुंचा दिया था। यह दौर राष्ट्रीय खेल, हॉकी, के अवसान का दौर भी था। नब्बे के दशक से भारत में आर्थिक उदारवाद के नाम पर मुनाफ़ाखोर बाज़ार का प्रभुत्व लगातार बढ़ता रहा। बाज़ार को ब्रांड एम्बैस्डर चाहिये था और सामने एक लोकप्रिय खेल का लोकप्रिय हीरो बन रहा था। सचिन ब्रांड इसी मिश्रण का नाम है।

एक बड़ा ब्रांड बाज़ार की वस्तुओं में 'मूल्य' का योगदान करता है। यानी, वस्तु की जरूरत तो उसकी लागत से जुड़ी होती है पर इसकी कीमत तय होती है 'मूल्य' जोड़ कर। यह 'मूल्य' सचिन ब्रांड के नाम से कई गुणा जोड़ा जा सकता है। बाज़ार के लिये सचिन तेंदुलकर की यही उपयोगिता रही। दरअसल क्रिकेट में निवेशकों का जमकर पैसा आना भी सचिन की इसी बाज़ारी छवि से संभव हुआ।

ले-देकर सचिन भारतीय क्रिकेट और भरतीय बाज़ार के लिये सोने के अंडे देने वाली ऐसी मुर्गी साबित हुआ जिसे कोई भी खोना नहीं चाहेगा। लिहाज़ा खेलने से सन्यास के बाद भी न क्रिकेट प्रशासन सचिन को छोड़ेगा और न ही बाज़ार।

एक सवाल यह भी उठता है कि सचिन अपने यश, और नाम का इस्तेमाल देश के करोड़ों बदहालों, जो उनके प्रशंसक भी हैं, के हक में करेंगे? दूसरे शब्दों में क्या वे भ्रष्टाचार, कुप्रशासन, साम्प्रदायिकता, शोषण, बेरोज़गारी, महंगाई इत्यादि मसलों पर कभी जुबान खोलना चाहेंगे। लगता तो नहीं है कि ऐसा होगा। क्योंकि, एक ब्रांड अन्ततः बाज़ार के हक में ही तो काम करेगा।

उत्तरी कोरिया में युद्ध टालने का कर्तव्य

आज के दौर में मानवता जिन बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, मैंने उनकी चर्चा कुछ दिन पहले ही की थी। हमारी धरती पर बौद्धिक जीवन लगभग 2,00,000 वर्ष पहले उत्पन्न हुआ था, हालांकि नयी खोजों से कुछ और ही बात का पता चला है।

हमें बौद्धिक जीवन और उस सामान्य जीवन के अस्तित्व के बीच भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो अपने शुरूआती रूप में हमारे सौर मंडल के अंदर करोड़ों साल पहले से मौजूद था।

दरअसल पृथ्वी पर जीवन के अनगिनत रूप मौजूद हैं। दुनिया के अत्यन्त जाने-माने वैज्ञानिकों ने बहुत पहले ही अपनी श्रेष्ठ रचनाओं में इस विचार की कल्पना की थी कि 13.7 अरब वर्ष पहले जब ब्रह्माण्ड की सृष्टि के समय जो महा विस्फोट हुआ था, उस समय उत्पन्न हुई ध्वनि को पुनरुत्पादित किया जा सकता है।

यह भूमिका काफ़ी विस्तृत होती, लेकिन यहां हमारा मकसद कोरयाई प्रायद्वीप में जिस तरह की परिस्थिति निर्मित हुई है, उसमें एक अविश्वसनीय और असंगत घटना की गम्भीरता को व्याख्यायित करना है, जिस भौगोलिक क्षेत्र में दुनिया की लगभग 7 अरब आबादी में से पांच अरब आबादी रहती है। यह घटना अब से 50 वर्ष पहले, 1862 में क्यूबा के इर्द-गिर्द उत्पन्न अक्टूबर संकट के बाद पैदा हुई नाभिकीय युद्ध की गंभीर चुनौती से मिलती-जुलती है।

1950 में वहां (कोरियाई प्रायदीप में) एक युद्ध छेड़ा गया था जिसकी कीमत लाखों लोगों ने अपनी जान देकर चुकायी थी। अमरीका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी शहरों के निहत्थे लोगों पर दो नाभिकीय बम गिराये जाने के कुछ ही सेकण्ड के अंदर लाखों लोगों की या तो मौत हुई थी या वे विकिरण के शिकार हुए थे जबकि इस घटना के महज पांच साल बाद ही कोरिया में युद्ध थोपा गया था।

उस युद्ध के दौरान जनरल डगलस मैकार्थर ने कोरिया जनवादी जन गणराज्य पर भी नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल करना चाहा था। लेकिन हैरी ट्रूमैन ने इसकी इजाजत नहीं दी थी।

इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि चीन ने अपने देश की सरहद से लगे एक देश में अपने दुश्मन की सेना को पैर जमाने से रोकने के प्रयास में अपने दस लाख बहादुर सैनिकों को गवां दिया था। सोवियत सेना ने भी अपनी ओर से हथियार, वायु सैनिक सहयोग, तकनीक और आर्थिक मदद दी थी।

मुझे गर्व है कि मैं एक ऐतिहासिक व्यक्ति, अत्यंत साहसी और क्रान्तिकारी नेता किम इल सुंग से मिला था। अगर वहां युद्ध छिड़ गया तो उस महाद्वीप के दोनों ओर की जनता को भीषण बलिदान देना पड़ेगा, जबकि उनमें से किसी को भी इससे कोई लाभ नहीं होगा। कोरिया जनवादी जन गणराज्य हमेशा से क्यूबा का मित्र रहा है तथा क्यूबा भी हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है और आगे भी रहेगा। अब जबकि उस देश ने वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, तब हम उसे उन तमाम देशों के प्रति उसके कर्तव्यों की याद दिलाना चाहेंगे, जो उसके महान दोस्त रहे हैं और उसका यह भूलना अनुचित होगा कि इस तरह का युद्ध खास तौर पर इस ग्रह की सत्तर फ़ीसदी आबादी को प्रभावित करेगा। अगर वहां इस पैमाने की लड़ाई फूट पड़ती है, तो दूसरी बार चुनी गयी बराक ओबामा की सरकार ऐसी छवियों के सैलाब में डूब जायेगी जो उनका अमरीका के इतिहास के सबसे मनहूस चरित्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। युद्ध को टालना उनका और अमरीकी जनता का भी कर्त्तव्य बनता है।

-फ़िदेल कास्त्रो रुज
-4 अप्रैल, 2013
(मूल अंग्रेजी लेख डायन्यूक डॉट ऑर्ग से आभार सहित।)